3086

SHRI RAJASEKHARAN: May I know whether it is a fact that the Government of India sponsored and supported with reference to the election to the post of Director General the nomination of Chile; if so, may I know the reasons for supporting the Chile candidate who ultimately was defeated?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: We sponsored the name of Shri B. R. Sen.

MR. SPEAKER: That was answered twice.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: Thereafter, for the elections any nation can support any other nation.

RELEASE OF SUGAR TO HALWAIS IN DELHI

*303. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

- (a) the quantity of sugar released to Delhi for Dusehra-Diwali functions:
- (b) whether Government have received reports that 70 per cent of the sugar supplied for the manufacture of sweetmeats was sold in the black market:
- (c) whether it is also a fact that the Halwais who manufactured for less quantity of sweetmeats for supply controlled rates, sold large quantities in black market and that barfi was sold at the rate of Rs. 25 per kilogram:
- (d) whether Government have made any investigations into these malpractices; and
 - (e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRI-CULTURE, COMMUNITY DEVE-LOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE):

- (a) 12,600 quintals,
 - (b) No, Sir.
- (c) to (e). The Delhi Administration have received a few complaints regarding sale of sweetmeats at rates .

higher than those fixed by it and the Administration is taking action in such cases. No complaint has, however, been received sale of Barfi at Rs. 25 per kilogram.

श्री प्रेम चन्द वर्मा: क्या यह सही है कि दिल्लो एडमिनिस्टेशन ने अपने काउंसिलरों को दो हजार से लेकर तीन हजार क्विटल तक चीनी अपने लोगों को बांटने के लिए दी ? क्या यह भी सही है कि वह चीनी काउंसिलरों ने अपने रिश्तेदारों को और पार्टी वर्कर्ज को बौर दोस्तों को बोगस तरीके से एलाट की और डेढ रुपये किलो चीनी खरीद कर छ: रुपये किलो तक बेची ? मैं जानना चाहता हं कि क्या इस तरह की श्रिकायतें सरकार को मिली हैं? क्या यह भी सही है कि एक-एक काउंसिलर ने दस हजार रुपये से लेकर बारह हजार रुपये तक इस भगर स्कैंडल में कमाया है ? मैं जानना चाहता हं कि क्या भारत सरकार इस सिलसिले में कोई ज्याडिशल इनक्वायरी कराने के लिए तैयार है ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN We have no RAM): information about it.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : दिल्ली और हिमाचल प्रदेश दोनों ही यूनियन टैरिटरीज हैं और दोनों की आबादी लनभग बराबर है। 12.600 टन चीनी दिल्ली को एलाट की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को जिसकी आबादी भी दिल्ली के बराबर है, कितनी चीनी एलाट की गई है ?

ANNASAHIB SHINDE: SHRI Sir, these special allotments were made uniformly all over the country for festivals and 20 per cent of the monthly quota was allotted to each State proportionately.

श्री प्रेम चन्द वर्माः मैंने पृष्ठा था कि हिमाचल प्रदेश को जितनी चीनी एलाट की गई है। इन्होंने परसटेन बता दिया है।

MR. SPEAKER: The hon. Minister has said that every State was given 20 per cent more, Himachal Pradesh also must have got 20 per cent more.

श्री हुकम चन्द कछवाय: क्या यह सही है कि दिल्ली प्रशासन ने जितनी चीनी मांगी श्री उतनी चीनी आपने उसको नहीं दी? कितनी चीनी की उन्होंने मांग की श्री और कितनी आपने दी।

आपने अपने उत्तर में बताया है कि कुछ मामले आए हैं और उन मामलों में कार्रवाई की जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी कार्रवाई की जा रही है और कितने मामले सामने आए हैं?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I will reply to the first part of the hon. Member's question,

भी कंवर लाल गुप्त: अध्यक्ष महोदय, जितने बड़े बड़े हलवाई हैं सब कांग्रेसी हैं?

MR. SPEAKER: There is nothing like Congress or any other party in this. It is about Delhi and all people are there.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Blackmarketeers and the Congress are one.

SHRI MANUBHAI PATEL: In Delhi it is Jan Sangh. (Interruption).

MR. SPEAKER: Delhi consists of all parties. Let us not go that way.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: As far as the first part of the hon. Member's question is concerned, may I submit for the information of the House that we have been giving the most preferential treatment to Delhi?

SOME HON. MEMBERS: Why?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: So, the complaint of the hon, Member that less sugar was allotted to Delhi is not at all justified

श्री हुकम चन्द कछवाय: कितनी मांगी थी और कितनी दी गई, यह मैंने सवाल पूछा था। श्री जगजीवन राम: जितनी चीनी की भी मांग की हो लेकिन राज्य सरकारें जितनी चीनी की मांग करती हैं उतनी उनको नहीं मिलती हैं। यह बात सही है कि दिल्ली को दूसरों के अनुपात से ज्यादा चीनी मिलती रही है और हम देते रहे हैं दूसरी बात उन्होंने यह पूछी है कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर को माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं। कार्रवाई जो है वह दिल्ली एडिमिनिस्ट्रेशन करने वाली है।

भी हुक्स चन्द कछवाय : कितने केसिस हैं ?

श्री जगजीवन राम : इसके लिए नोटिस दीजिये।

को हुन्म चन्द कछ शय: मंत्री महोदय कितनी चीनी लेते हैं हर महीने ?

बन्यक महोदय: आप भी तो नेते हैं।

भी सरबू पांडेप: क्या यह सही है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा दीवाली के मौके पर तो वीनी रिलीज की गई थी लेकिन बकरीद के मौके पर मुसलमानों को चीनी नहीं मिली और इसके बारे में शिकायते भी आई हैं? अगर यह सही है तो इसके बारे में क्या कार्यवाई की गई है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE:
We do allot additional quotas for festivals. But, so far as the distribution arrangements are concerned it is for the Delhi Administration to see that all communiques are properly served from the additional quota that is given by us.

श्री सनुषाई पटेल: दिल्ली के चीफ एग्जे-विटव काउंसिलर श्री मल्होता के कुछ ओवर-एंध्यूसिएस्टिक साथियों ने जो यह कहा था कि यहां कोई ब्लैक मार्किट बगैरह चीनी की नहीं हुई है उसके बारे में क्या यह सही नहीं है कि श्री मल्होता ने एक स्टेटमेन्ट निकाली थी यदि हां तो क्या सरकार का ब्यान उस स्टेटमेंट की तरफ गया। SHRI ANNASAHIB SHINDE: We are not aware of this statement of the Chief Executive Councillor.

SHRI NAMBIAR: In view of the fact that there is serious difficulty in securing sugar for the common man and in view also of the fact that government is thinking of what is known as partial de-control, may I know whether it is possible for the people to get a little more sugar without going to the blackmarket and paying Rs. 6 to 8 per kilo? Has the government thought about it? Is there any plan to ensure better distribution of sugar to the common man?

MR. SPEAKER: This question relates to release of sugar to halwais and his question relates to supply of sugar to common people.

SHRI NAMBIAR: I am asking about the policy of distribution.

SHRI SAYYAD ALI: I want to know from the Food Minister whether he is going to release sugar for Ramzan.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: Some additional quantities have been allotted for this purpose.

SHRI GADILINGANA GOWD:
After partial de-control of sugar, ration shops in Delhi are not at all supplying sugar. What is the reason?

SHRI JAGJIWAN RAM: For supply by ration shops some quantity has been allotted to Delhi Administration, though it is on a reduced scale. What we were distributing previous to this arrangement was 1,59,000 tonnes for the whole country. Now we are distributing 100,000 tonnes. Therefore, there has been proportionate reduction in supply by the ration shops.

SHRI GADILINGANA GOWD: I was told by the ration shop in South Avenue that there is no sugar in the ration shop.

SHRI PILOO MODY: Because they have been more favourable to the North Avenue.

श्री क० ना० तिबारी: देम, में 29 लाख टन चीनी की खपत है और साढ़े 22 लाख टन चीनी पैदा होती है। अभी मंती महोदय ने कहा है कि दिल्ली को ज्यादा चीनी मिलती है। मैं जानना चाहता हूं कि शार्टेंज के बावजूद भी दिल्ली को कितने परसेंट दी जाती हैं और दूसरे प्रान्तों को कितने परसेंट दी जाती है।

श्री जगजीवन राम: प्रोपोर्शनेटली सभी का कोटा कम किया गया है। जितना कम हुआ सभी राज्यों का बराबर ही घटाया गया है।

श्री प्रेम चन्द वर्मा: दिल्ली के लिए वह कह रहे हैं कि हम ज्यादा दे रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त: पहले जहां ढाई सौ ग्राम प्रति सप्ताह प्रति व्यक्ति चीनी दी जाती थी बब वह दो सौ ग्राम दी जाने लगी है। इसके अलावा शादी या और तरह से स्पेशन कोटा हलवाइयों को दिया जाता था या मैम्बर्ज को कोटा दिया जाता था । दिल्ली एडमिनिस्टेशन अब वह नहीं देती है। इस लिए कि उनको केवल राशन के लिए चीनी मिलती है, और किसी चीज के लिए नहीं। दिल्ली एडमिनिस्टेशन ने मंत्री महोदय से कहा है कि उन को और शुगर का कोटा दिया जाये । क्या मंत्री महोदय दिल्ली की स्पेशल कन्डीशन्ज को देखते हए या तो दिल्ली एडमि-निस्टेशन को दिल्ली के लिए और कोटा देंगे और या सीघे हलवाइयों को कोटा देंगे, जिन को इस वक्त कुछ नहीं मिलता है, जिस की वजह से मिठाइयों के दाम बहत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्यों कि दिल्ली में औपन मार्केट में चीनी का भाव पांच और छ: रुपये है ?

श्री जगलीवन राम : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इतनी जानकारी है कि चीनी के मामले में दिल्ली को भी उसी नीति के भीतर लाया गया है, जिसमें सारे देश को लाया गया है । इसलिए अगर दिल्ली एडिंग-निस्ट्रेशन के एक्सिक्यूटिव कौंसिलजं कुछ कह दें, तो क्या इसी लिए हम उनको विशेष कोटा दें दें? यह बात माननीय सदस्य को

खुद समझनी चाहिए । हमने उनको उतना ही दिया है, जितना कि सारे देश को दिया है। चीनी काटने के बाद जो प्रोपोर्शनेट पड़ता है, उतना दिल्ली एडिमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है। लेकिन चूंकि दिल्ली को पहले से ही ज्यादा मिलता रहा है, इस लिए काटने के बाद भी बौर राज्यों के मुकाबले में दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को अधिक मिलता है। जहां तक हलवाइयों का सम्बन्ध है, वे फ्री शूगर में से खरीदें और डामेस्टिक कनज्यूमर्ज को हम राशन में देंगे।

WAGE BOARD FOR CEMENT INDUSTRY

+

*304. SHRI UMANATH: SHRI E. K. NAYANAR: SHRI K. RAMANI: SHRI P. P. ESTHOSE;

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

- (a) whether the Second Wage Board for Cement Industry has submitted its report;
- (b) if so, whether Government have taken any decision thereon;
- (c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay; and
- (d) when the report is likely to be submitted?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI): (a) Yes, Sir. The report of the Wage Board was submitted to the Government on 14th August, 1967.

- (b) The recommendations made in the report are being examined.
 - (c) and (d). Do not arise.

SHRI UMANATH: In view of the fact that after the appointment of this Wage Board the submission of the report has taken such a long time and the

workers had no relief whatsoever, I would like to know whether Government have fixed any time limit for their consideration and decision; if so, when do the Government hope to announce their decision in this regard?

SHRI HATHI: The decision will be announced, I hope, very shortly—within a fortnight or so. That is my expectation. Secondly, perhaps interim relief was given.

SHRI UMANATH: No interim relief was given. That is why I am asking this.

SHRI HATHI: No; it was given — 5.48 to all the workers covered by the First Wage Board with effect from the 1st January, 1965.

SHRI UMANATH: In the Indian Labour Conference with regard to these wage boards the understanding is that once a wage revision is made, for five years there should not be any revision. That means, immediately after five years they are entitled to a second wage revi-Now, the wage boards are free to make their own recommendation as to the date of implementation. would like a know from the Government, since according to this understanding at the Indian Labour Conference the workers will be entitled to a second revision immediately after five whether Government assure this House that whatever recommendations are finalised the decision or agreement of the unions will be implemented with retrospective effect, that is, from the date of appointment of this Commission.

SHRI HATHI: I think, the Wage Board will take this into consideration; they will also recommend the date of implementation of the award.

SHRI UMANATH: My question is whether Government will assure this House—it is in the hands of the Government—that irrespective of the recommendation of the Commission, since the understanding at the Indian Labour Conference is that immediately after five years they will be entitled to an-